प्रतिलेखन संख्या 15

अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है वरन, वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हम अमरीका को ले सकते हैं। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा, जो उधार पर माल ले सकते हों। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढँग से सरकार चलाएँगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। हमने कर भी लगा दिए और प्रसार भी कर दिया। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें।

श्रीमन, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है? क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंयाचत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मतातिधकर के आधार पर यू एन ओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से

कर लगा कर एक किस का खाता खोल दिया जाए? जो देश विकसित हैं उनके मजदूरों का एक घ

ंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन हैं।

इसलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी

और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और

गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें

परेशानी होती है इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे। लेकिन पश्चिमी जर्मनी न तो

अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि

अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए? आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता

हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ।